गठबंधन (संप्रग) की सरकार नहीं चाहते हैं, उन्हें अपना रुख सार्वजनिक करना चाहिए, न कि पीठ पीछे बातें करके भ्रम पैदा करना चाहिए. इसने कहा गया कि जो लोग भाजपा से लड़ रहे हैं, अगर उनका भी मानना है कि

शुक्रवार को कांग्रेस पर प्रहार करते हुए कहा कि यह 'डीप फ्रीजर' में चली गयी है. तृणमूल के मुखपत्र ने हाल में दावा किया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ ममता बनर्जी चेहरा बनकर उभरी हैं, न कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी. शिवसेना ने कहा : सुश्री बनर्जी के मुंबई

पर निर्णय किया जाना चाहिए. यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा कांग्रेस को हराने के लिए काम करते हैं, तो कोई भी इसे समझ सकता है, क्योंकि यह उनके एजेंडा का हिस्सा है, लेकिन जो लोग मोदी और भाजपा के खिलाफ हैं और कांग्रेस के बारे में बुरा सोचते हैं, तो यह सबसे बड़ा खतरा है.

दिव्यांगों को शिक्षा की मुख्यधारा में लाने की जरूरत : डॉ सोमा बंद्योपाध्याय

कोलकाता. इंटरनेशनल वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे के उपलक्ष्य में शनिवार को दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया गया. 'विजन 2021 : न्यूलुक टुवॉड्र्स डाइवरसिटी एंड इनक्लूजन' विषय पर आयोजित यह कार्यक्रम नेताजी सुभाष ओपन यूनिवर्सिटी और इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स के संयुक्त तत्वावधान में ऑनलाइन मोड में किया गया. इस कॉन्फ्रेंस में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित डब्ल्यूबीयूटीटीईपीए (वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग, एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन) की वाइस चांसलर प्रो डॉ सोमा बंद्योपाध्याय ने कहा कि समाज में आम लोगों के साथ दिव्यांग लोग भी हैं, जिनके जीवन में कई तरह की चुनौतियां हैं. चुनौतियों के बाद भी कई बार वे सफलता के नये स्तंभ गढ़ लेते हैं. ऐसे दिव्यांग बच्चों को भी प्रोत्साहित करने की जरूरत है. दिव्यांग यानी मेंटली-फिजिकली चैलेंज्ड बच्चों को आम छात्रों की तरह शिक्षा की मुख्यधारा में लाया जाये, तो वे भी बहुत कुछ कर सकते हैं. जिस तरह से पैरालिंपिक में कई दिव्यांग खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन कर मेडल हासिल किये. समाज के दिव्यांगों को मुख्यधारा में लाने से उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा. यह सामाजिक बदलाव के लिए एक बहुत बड़ी कोशिश है.नेताजी ओपन यूनिवर्सिटी के सीडीएसईआर सेंटर के निदेशक अतिंद्र नाथ डे ने कहा कि दिव्यांगों को लेकर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी मुद्दा उठाया गया है. समाज का एक वर्ग इस श्रेणी में भी आता है. इस संदर्भ में राज्य सरकार द्वारा जारी की गयीं नीतियों को क्रियान्वित करने की जरूरत है. सरकारी व गैर सरकारी स्तर पर दिव्यांगों के लिए जो काम हो रहे हैं, उन्हें भी आगे ले जाने की जरूरत है. कार्यक्रम में रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से फिलीपींस के डॉ जे संतोष ने भी अपने विचार रखे. मौके पर आरसीआइ, भुवनेश्वर (पूर्वी क्षेत्र) के डॉ पीयूष जैन के साथ अन्य विशेषज्ञों ने भी संबोधित किया.

वेबिनार में भाग लेते अतिथि.

व गैर शिक्षा कर्मियों के ट्रांसफर की जारी की अधिसूचना